एक्ज़िम बैंक EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

एक्ज़िमिअस

निर्यात लाभ

जून 2019
खंड XXXV अंक II

इस अंक में

1 भारत-म्यांमार व्यापार और निवेश: संभावनाएं एवं आगे की राह
3 भारतीय निर्यातों पर नॉन-टैरिफ उपाय
5 चुनिंदा क्षेत्रों पर बजट का प्रभाव
6 कृषि और कृषि मशीनीकरण में भारत-अफ्रीका साझेदारी
8 कृषि और कृषि मशीनीकरण में भारत-अफ्रीका साझेदारी
9 एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं
10 तिमाही गतिविधियां
12 बिम्सटेक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार
13 मुद्रा की प्रवृत्तियां
14 चुनिंदा देशों का आर्थिक परिदृश्य
15 आंकड़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था
16 व्यापार और भागीदारी अवसर

भारतीय निर्यात-आयात बैंक
का तिमाही प्रकाशन
www.eximbankindia.in

प्रधान कार्यालय :
केंद्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई 400 005
Tel.: 022 2217 2600
Email : ccg@eximbankindia.in

भारत-म्यांमार व्यापार और निवेश: संभावनाएं एवं आगे की राह

म्यांमार दक्षिणपूर्वी एशियाई देश है, जो अपनी भौगोलिक स्थिति के चलते लाभ की स्थिति में है। क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई बाजारों के बीच रणनीतिक पुल का काम करता है। भारत आसियान बाजार तक पहुंचने के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण लिंक है। साथ ही भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का द्वार भी है। पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के जरिए भारत के साथ म्यांमार की 1600 किमी की भौगोलिक सीमा और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा लगती है।

आसियान क्षेत्र में म्यांमार सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस क्षेत्र के 2018 के जीडीपी में म्यांमार का हिस्सा 2.3% रहा और 2014-2018 के दौरान 6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कुछ नीतिगत कदमों के बाद विदेशी और घरेलू निवेश में बढ़ोत्तरी की आशा है और इसके चलते 2019-2023 के दौरान म्यांमार की औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.7% रहने का पूर्वानुमान है।

म्यांमार के साथ भारत के व्यापार संबंध

म्यांमार आसियान, बिम्सटेक और मेकोंग गंगा को-ऑपरेशन का सदस्य है। इस सदस्यता ने द्विपक्षीय संबंधों को क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय दिशा दी है और भारत की एक्ट ईस्ट नीति में एक महत्त्वपूर्ण पहलू जोड़ने का काम किया है। इसके अलावा, म्यांमार 2008 से पर्यवेक्षक के रूप में सार्क से भी जुड़ा हुआ है।

म्यांमार को भारत से निर्यात 2008 के 237.3 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2018 में 1.2 अरब यूएस डॉलर का हो गया और इसमें 17.9% की सीएजीआर दर्ज की गई। हालांकि म्यांमार से भारत द्वारा आयात में कमी आई है, जो 2008 में 906.3 मिलियन यूएस डॉलर का था और 2018 में घटकर 445.3 मिलियन यूएस डॉलर का रह गया **(चार्ट 1)**।

भारत द्वारा 2018 में म्यांमार को निर्यातित वस्तुओं में प्रमुख रूप से खनिज ईंधन, तेल और इसके उत्पाद, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, चीनी और मिठाइयां शामिल रहे। म्यांमार को भारत से कुल निर्यातों में इनका हिस्सा 44% रहा। भारत से 2018

चार्ट 1: म्यांमार के साथ भारत के व्यापार

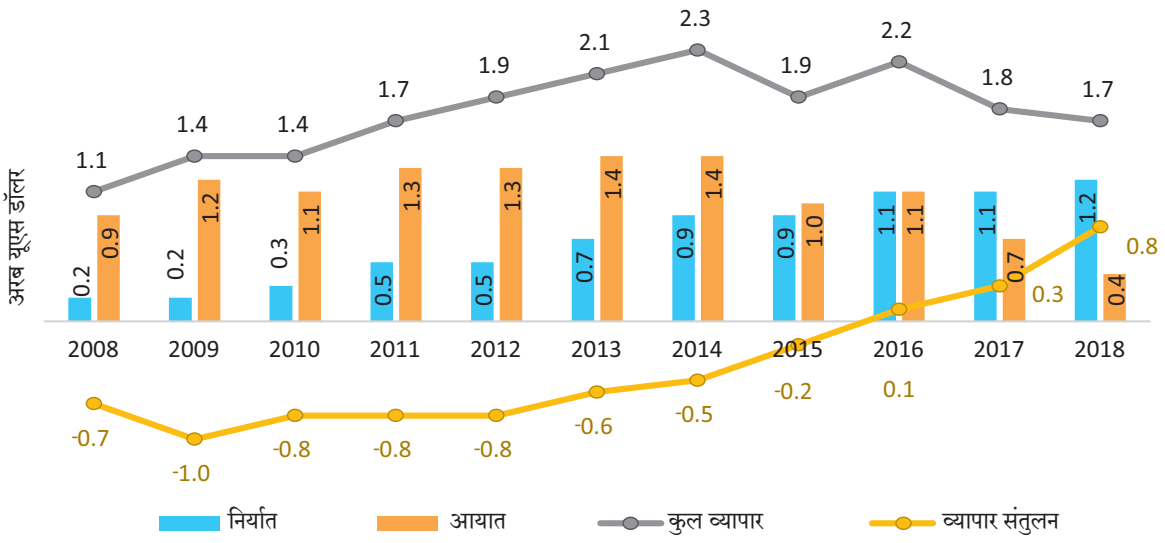

स्रोत: आईटीसी ट्रेडमैप, यूएन कॉमट्रेड और एक्ज़िम बैंक विश्लेषण

में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा आयातक म्यांमार ही रहा। म्यांमार सरकार ने 2015 में भारत और थाईलैंड से चीनी और डीजल जैसी वस्तुओं के आयात को मंजूरी प्रदान की थी, ताकि इनकी भारी मांग को पूरा करने के लिए इन्हें म्यांमार से पुनः निर्यात किया जा सके और निर्यात आय बढ़ाई जा सके। किन्तु 2018 में म्यांमार के वाणिज्य मंत्रालय ने चीनी में आई गिरावट को स्थिर करने के लिए इसके पुनः निर्यात पर रोक लगा दी। आने वाले समय में भारत से म्यांमार को निर्यातों पर इसका असर दिख सकता है।

वहीं, म्यांमार से भारत द्वारा किए जाने वाले आयातों में प्रमुख रूप से खाद्य वनस्पति तेल, कुछ कंद-मूल तथा लकड़ी और लकड़ी की वस्तुएं शामिल हैं। म्यांमार से भारत द्वारा 2018 में आयातित कुल वस्तुओं में इनका हिस्सा 88% है।

भारत ने 2017 में खाद्य वनस्पति के अंतर्गत श्रेणीबद्ध फलियों और दालों तथा कंद-मूलों (एचएस 07) के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगा दिया था, जिन्हें मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

- ***भारत-म्यांमार सीमा व्यापार***

म्यांमार की सीमा पांच पड़ोसी देशों से लगती है- भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और लाओ पीडीआर। म्यांमार का 50% से अधिक निर्यात और करीब 70% आयात चीन, थाईलैंड और भारत के साथ होता है।

भारत और म्यांमार के बीच 1994 में एक सीमा व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो 12 अप्रैल, 1995 से प्रभावी हुआ। इस करार के मुताबिक भारत में मोरे (म्यांमार-तामु) और जोखावथर (म्यांमार-रीह) दो सीमा व्यापार बिंदु हैं। अवाखुंग-पंसत / सोमरा पर तीसरे सीमा व्यापार बिंदु की स्थापना करने पर भी सहमति बनी थी। वर्तमान में म्यांमार के साथ अधिकांश व्यापार मोरे (भारत के मणिपुर में) के जरिए होता है।

आरबीआई ने 5 नवंबर, 2015 को वस्तु विनिमय व्यापार को खत्म कर दिया था, जो भारत-म्यांमार के बीच सीमा व्यापार का हिस्सा था। फिर 17 दिसंबर, 2015 को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने मोरे पर सीमा व्यापार को सामान्य कर दिया। इससे भारत की ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम और आसियान-भारत वस्तु व्यापार करार प्रासंगिक हो गए और पूर्ववर्ती सीमा लागू नहीं रही।

स्थानीय व्यापार को सुगम बनाने में बॉर्डर हाट भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राज्य सरकारों द्वारा विदेश मंत्रालय को सुझाई गई 15 बॉर्डर हाटों में से अरुणाचल प्रदेश में पंग्सू पास और मणिपुर में सोमराई को मंजूरी मिली है।

भारत सरकार के इन प्रयासों के बावजूद, भारत-म्यांमार सीमा पर व्यापार, चीन-म्यांमार और थाई-म्यांमार सीमा पर व्यापार की तुलना में कम रहा।

म्यांमार के साथ अधिकांश व्यापार समुद्री मार्ग के जरिए रहा। न्हावा शेवा (जेएनपीटी) म्यांमार का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है, जिसके द्वारा वर्ष 2017-18 में कुल निर्यात का 19.9% तथा आयात का 34.1% व्यापार किया गया।

म्यांमार और भारत को जोड़ने वाली परियोजनाएं

भारत की एक्ट-ईस्ट नीति को बढ़ावा देने और दक्षिणपूर्वी एशियाई बाजारों को भू, जल और वायु मार्ग से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने कई परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें से अन्य के साथ-साथ कुछ परियोजनाएं इस प्रकार हैं- भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग तथा भारत के पूर्वी बंदरगाहों से म्यांमार और पूर्वोत्तर को कार्गो पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था के लिए कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना, गोलाघाट से दिमापुर, इंफाल होते हुए मोरे और गुवाहाटी से नागांव (भारत-बांग्लादेश सीमा पर) होते हुए दावकी - शिलांग औद्योगिक कॉरिडोर और मेकोंग-भारत आर्थिक कॉरिडोर।

म्यांमार में भारत का निवेश

अप्रैल 1996 से मार्च 2019 के दौरान म्यांमार में संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी संस्थाओं में इक्विटी, ऋण तथा गारंटियों सहित मंजूर संचयी भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 369.2 मिलियन यूएस डॉलर का रहा। वहीं दूसरी ओर, अप्रैल 2000 से मार्च 2019 के दौरान म्यांमार से भारत को संचयी अंतःप्रवाह 9 मिलियन यूएस डॉलर का रहा।

म्यांमार के साथ भारत का व्यापार बढ़ाने के लिए संभावित वस्तुएं

भारत से म्यांमार को निर्यात बढ़ाने के लिए संभावित वस्तुओं में मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण (एचएस 85), मशीनरी और मैकेनिकल एप्लायंस (एचएस 84), प्लास्टिक और प्लास्टिक की वस्तुएं (एचएस 39), लोहे और स्टील की वस्तुएं (एचएस 73), पशु और वनस्पति वसा तथा तेल (एचएस 15), मानव निर्मित फिलामेंट (एचएस 54) और मानव निर्मित स्टैपल फाइबर (एचएस 55) शामिल हैं।

म्यांमार में भारत का निवेश बढ़ाने के लिए रणनीति

म्यांमार में भारत का निवेश अब तक कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है। म्यांमार में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में किए गए उपायों से भारत को लाभ मिल सकता है। इस पृष्ठभूमि में ऐसे कुछ क्षेत्र जिनमें भारत म्यांमार में अपने निवेश बढ़ा सकता है, निम्नलिखित हैं:

- ***विनिर्माण क्षेत्र और कृषि आधारित उद्योग***

चीन-यूएस के व्यापार युद्ध और चीन में बढ़ते वेतन के चलते विनिर्माता वैकल्पिक स्थानों की तलाश में हैं। ऐसे में म्यांमार निवेश के लिए अच्छी जगह है। भारतीय विनिर्माता म्यांमार में दुपहिया, तिपहिया वाहनों के विनिर्माण, सीमेंट, फर्नीचर, एफएमसीजी उत्पादों, कृषि मशीनों का विनिर्माण और असेंबलिंग तथा कपास और रेशम जैसे क्षेत्रों में आगामी अवसरों को भुना सकते हैं।

- ***प्राकृतिक संसाधन विकास***

म्यांमार में पेट्रोलियम और गैस भंडारों के साथ-साथ खनिज और ऊर्जा संसाधनों के विपुल संसाधन हैं। यहां बड़ी जल-विद्युत परियोजना की भी अच्छी संभावना है। खनिज संसाधनों के विकास / उत्खनन में भारत और म्यांमार के बीच बाय-बैक जैसे द्विपक्षीय समझौतों के साथ बढ़ा सहयोग वाणिज्यिक संबंध बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण रणनीति हो सकती है।

- ***इंफ्रास्ट्रक्चर***

भारत और म्यांमार के बीच वस्तुओं के सुचारू परिवहन के लिए सीमा पर बुनियादी ढांचे में सुधार करने की अत्यंत आवश्यकता है। यहां आधुनिक भंडारण सुविधाओं के साथ भू-बंदरगाह का विकास, खाद्य परीक्षण सुविधा, सूचना प्रौद्योगिकी और टेलीकॉम सपोर्ट, नियमित बिजली आपूर्ति, माल से लदे ट्रकों के वजन के लिए कांटे तथा सड़कों और पुलों के विकास जैसी कुछ जरूरी प्रमुख बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का विकास करना आवश्यक है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) और लैंड कस्टम स्टेशन (एलसीएस) जैसी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के अभाव को पूरा करने तथा व्यापार का सुगमीकरण करने की भी जरूरत है। उत्पादों के लिए मूल देश (कंट्री ऑफ ऑरिजिन - सीओओ) को लागू करना भी महत्त्वपूर्ण है।

परिचय

गैर–टैरिफ उपाय (एनटीएम) निर्यातकों और विशेष रूप से विकासशील देशों के निर्यातकों के लिए बड़े महंगे साबित होते हैं। फिर भी विकसित और विकासशील दोनों देश सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और ऐसे ही अन्य विषयों के सिलसिले में सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आयातों पर गैर–टैरिफ उपाय लागू करते हैं। किन्तु वास्तविकता यह है कि एनटीएम प्रायः घरेलू उत्पादकों के संरक्षण के लिए लगाए जाते हैं। दरअसल गैर टैरिफ उपायों और गैर–टैरिफ बैरियरों के बीच बहुत मामूली अंतर होता है। एनटीएम के लिए होने वाली चर्चा में प्रायः एक पक्ष इसे लागू करने का बचाव करता है, तो वहीं दूसरा पक्ष यह साबित करने का प्रयास करता है कि ये उपाय व्यापार के सुचारू संचालन में बाधाएं उत्पन्न करेंगे।

व्यापार और टैरिफ पर सामान्य करार (गैट) को प्राथमिक रूप से आयात शुल्क (टैरिफ) कम करने के लिए लागू किया गया था, जो विभिन्न देशों ने अपने उत्पादकों के संरक्षण के लिए लागू किए थे। साथ ही इसका उद्देश्य राष्ट्र को अपने संप्रभु कार्यकलापों के लिए निधि जुटाने में मदद करना भी था। व्यापार करने वाले देशों ने अपने टैरिफ उल्लेखनीय रूप से कम किए, ताकि सीमाई व्यापार में वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा मिले। जैसे ही टैरिफ उल्लेखनीय रूप से कम हुए, वैश्विक व्यापार पर इन गैर–टैरिफ उपायों का विपरीत असर पड़ा। ये उपाय कानून, विनियम और विनियामकीय पद्धतियां बनाकर विभिन्न नीतिगत उपायों के जरिए गए थे और माना गया था कि ये राष्ट्रहित में किए जा रहे हैं, किन्तु प्रायः इनका प्रयोग सीमा पर नई बाधाएं पैदा करने के लिए किया गया।

टैरिफ

एक तरफ किसी देश को अपने निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए गैर–टैरिफ बाधाओं से निपटना अत्यावश्यक हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ टैरिफ भी उनका ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। आम तौर पर माना जाता है कि विकसित देशों में टैरिफ काफी कम हो गए हैं और विकासशील देशों में ये अब भी काफी अधिक हैं। यद्यपि यह राय वास्तविकता से पूरी तरह भिन्न नहीं है, तथापि विकसित देशों में भी देखा जा सकता है कि बहुत से टैरिफ अत्यधिक हैं, जो विकासशील देशों से निर्यातों के लिए बड़ी बाधाओं का काम करते हैं।

कोई भी देश कई उद्देश्यों से टैरिफ लगाता है। विकासशील देशों में वे अपने घरेलू नव उद्योगों के संरक्षण के लिए टैरिफ लगाते हैं और उन्हें बढ़ने का मौका देते हैं। साथ ही दूसरे देशों से मिलने वाली प्रतिद्वंद्विता से निपटने में भी मदद करते हैं। टैरिफ प्रायः आयात के विकल्प पर आधारित औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों के आधार पर बाधा उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता रहा है। जैसा कि हाल ही में अमेरिका ने एल्यूमीनियम और स्टील पर टैरिफ लगाकर किया।

भारत से प्रमुख आयातक देशों में निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर औसत और उच्चतम टैरिफ के विश्लेषण से पता चलता है कि वे देश के सामान्य औसत से भी अधिक हैं। उदाहरण के लिए, यूएसए का औसत टैरिफ 3% है, जबकि भारत से यूएस को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर औसत टैरिफ 4% है। इसी प्रकार यूरोपीय संघ का औसत टैरिफ 5% है, जबकि भारत से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर 8% है।

ऐसे देशों का अध्ययन भी किया गया जहां 6% से 15% तक मध्यम टैरिफ रेंज लागू है। वहां भी भारत से निर्यात किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाए गए हैं। उदाहरण के लिए, चीनी बाजार में कॉफी, चमड़ा और जूते–चप्पल, विभिन्न खाद्य पदार्थ और हल्के विनिर्मित उत्पादों पर 10% से अधिक टैरिफ है।

गैर–टैरिफ उपायों का वर्गीकरण

गैर टैरिफ उपायों में कई तरह के उपाय शामिल होते हैं, जो इन उपायों के लिए किए गए वर्गीकरण पर आधारित होते हैं। अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण में सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय; व्यापार के लिए तकनीकी बैरियर; प्री–शिपमेंट निरीक्षण और अन्य औपचारिकताएं; मूल्य नियंत्रण उपाय; लाइसेंस, कोटा, निषेध और अन्य मात्रा नियंत्रण उपाय; प्रभार, कर और अन्य पैरा–टैरिफ उपाय; वित्त उपाय; एंटी–प्रतिद्वंद्वी उपाय; व्यापार संबंधी निवेश उपाय; वितरण प्रतिबंध; बिक्री पश्चात सेवाओं पर प्रतिबंध; सब्सिडी (निर्यात सब्सिडी को छोड़कर); सरकारी प्रोक्योरमेंट प्रतिबंध; बौद्धिक संपदा; मूल उत्पादन स्थल के नियम; और निर्यात संबंधी उपाय शामिल होते हैं।

एनटीएम विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं, किन्तु निर्यातकों के लिए सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं– व्यापार के लिए तकनीकी बैरियर (टीबीटी) और सैनिटरी तथा फाइटोसैनिटरी उपाय (एसपीएस)। विश्व व्यापार संगठन के एसपीएस और टीबीटी करारों के अंतर्गत अन्य के साथ–साथ आयात लाइसेंस, व्यापार सुधार उपाय, मूल उत्पत्ति स्थल संबंधी नियम, निवेश उपाय और तकनीकी विनियम शामिल किए जाते हैं।

एक्ज़िम बैंक सर्वेक्षण के नतीजे

एक्ज़िम बैंक द्वारा बीते दिनों किए गए भारतीय निर्यातों पर गैर–टैरिफ उपाय शीर्षक शोध अध्ययन के दौरान 587 फर्मों का इंटरव्यू किया गया। इनमें से 75% ने माना कि उन्हें एनटीएम संबंधी समस्याएं हैं।

जिन फर्मों को इंटरव्यू किया गया, उनमें से अधिकांश छोटी फर्में थीं। अतः उनकी प्रतिक्रिया महत्त्वपूर्ण है। जो फर्में विस्तृत एसपीएस और टीबीटी को स्वयं चिन्हित नहीं कर पाईं उन्होंने बंदरगाह प्रतिबंध, पुष्टि विश्लेषण प्रक्रिया का सख्त इस्तेमाल आयातक देशों में विशिष्ट परीक्षण अथवा आयातक देश की विनियामक एजेंसी से इंस्पेक्टरों द्वारा निरीक्षण और इसकी लागत का वहन निर्यातक द्वारा किए जाने जैसे अन्य गैर–टैरिफ उपायों के जरिए गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी उपाय रिपोर्ट किए।

यह देखा गया है कि विकसित और विकासशील दोनों तरह के देशों में मानकों की जटिलता बढ़ रही है। किन्तु विकासशील देशों के निर्यातकों के सामने आने वाली समस्याएं अधिकांशतः टैरिफ, बंदरगाह पर मंजूरी अथवा व्यवस्थागत देरी से संबंधित होती हैं। विकसित देशों द्वारा अधिक सरल उपाय प्रयोग में लाए जाते हैं और उनकी पुष्टि विश्लेषण प्रक्रिया महंगी पूरी है। साथ ही से पूरा कर पाना भी कठिन है। कुछ मामलों में, इससे झींगों का कन्साइनमेंट खारिज होने जैसी चीजें भी सामने आई हैं। फिर उन फर्मों को स्वीकृत सूची में पुनः शामिल होने में सालभर तक का समय लग गया है।

प्राथमिक सर्वेक्षण में सामने आया है कि भारत के निर्यातक समुदाय की अंतरराष्ट्रीय व्यापार ईको-सिस्टम की समझ और जिस स्तर पर वे काम करते हैं, उसके अनुसार उनका आर्टिकुलेशन काफी अलग है। ग्रासरूट स्तर पर जाकर दर्ज की गई इस धारणा से कुछ सबक मिलते हैं। औसत निर्यातक को इससे फर्क नहीं पड़ता कि बाधा निर्यातक देश के व्यापार ईको-सिस्टम से है या आयातक देश से है या फिर इन दोनों के बीच कहीं है। अपने निर्यातों के सुचारू प्रवाह में किसी भी उपाय को यदि वह बाधा के रूप में देखता है तो इसका एक निश्चित लागत के रूप में उस पर असर पड़ता है, जिससे प्रक्रिया महंगी हो जाती है और इसकी बहुत संभावना रहती है कि वह बाजार उसके हाथ से निकल जाए। कुछ निर्यातक ऐसे भी होते हैं, जो गैर-टैरिफ उपायों के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं और उन्हें किसी बाधा के रूप में नहीं देखते हैं। इसके पीछे की वजह या तो यह है कि वे इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं या फिर उनके उद्यमिता के उत्साह के आगे ये बाधाएं कुछ नहीं होतीं। वे इन्हें सामान्य मान लेते हैं। तथापि, बहुत से निर्यातक गैर-टैरिफ उपायों के महंगे परिणामों को जानते हैं और उनसे बचने के बारे में सोचते हैं।

यह भी तथ्य है कि बहुत से निर्यातकों को उनके लिए उपलब्ध व्यापार के संस्थागत फ्रेमवर्क के बारे में तुलनात्मक रूप से कम जानकारी होती है और व्यापार नीति के फ्रेमवर्क में इसे एक प्रमुख कमी के रूप में बताया गया है। बहुत से निर्यातक अधिमानी व्यापार के लिए उपलब्ध बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र से अब भी अनभिज्ञ हैं। यहां तक कि जब वे अधिमानी तंत्र के अंतर्गत निर्यात कर रहे होते हैं, वे द्विपक्षीय व्यापार करार तथा यूनिलैटरल जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज (जीएसपी) के बीच भेद कर पाने में भी अक्षम होते हैं।

ये सभी बातें संस्थागत फ्रेमवर्क पर ही नहीं, बल्कि उत्पत्ति के मूल स्थान, गैर-टैरिफ उपायों और इन उपायों को समझने के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाने की जरूरत की ओर संकेत करती हैं।

गैर-टैरिफ उपायों का व्यापार प्रभाव

एक्ज़िम बैंक के शोध अध्ययन में एनटीएम के प्रभावों को समझने के लिए इन्वेंटरी आधारित फ्रीक्वेंसी उपाय का इस्तेमाल किया गया था। व्यापार सुरक्षा उपायों से प्रत्यक्ष समतुल्य टैरिफ मिलते हैं, इसलिए समग्र प्रभाव के आकलन के लिए प्रारंभ में इस प्रकार के सभी उपायों को कंप्यूटेबल जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क (सीजीई) में इस्तेमाल किया गया। घरेलू अर्थव्यवस्था में इनपुट की लागत को कम कर गैर-टैरिफ उपायों का सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। अर्थव्यवस्था-वार नकारात्मक और सकारात्मक प्रभावों के विश्लेषण से निम्नलिखित प्रभाव सामने आते हैं - निर्यातः -0.01%, आयातः -0.2%, रोजगारः -0.05%, जीडीपीः -0.02%, निर्यात क्षेत्रों का उत्पादनः -0.03%. समग्र रूप में भले ही ये आंकड़े छोटे दिखें, किन्तु क्षेत्रों पर इनका उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है।

निष्कर्ष

जब एनटीएम विनियमों के अनुपालन की बात आती है तो विकासशील देश गंभीर दुविधा में प्रतीत होता है। एक तरफ, व्यापार करने वाले देश अपने टैरिफ घटाते हैं और अपने बाजारों तक पहुंच को आसान बनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनटीएम अपनाने से अनुपालन लागत बढ़ जाती है और व्यापार के लिए नए प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ता है।

भारत जैसे विकासशील देश के लिए कुछ उपाय लागू कर इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। सबसे पहले इन उपायों के संबंध में सूचना, उनमें आने वाले परिवर्तन और उनसे निपटने के लिए रणनीतियां द्विवार्षिक रूप से जुटाई जानी चाहिए और निर्यातकों को उनकी संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों के माध्यम से पहुंचाई जानी चाहिए। दूसरा, सख्त मौजूदा और आगामी मानकों को लेकर रेड अलर्ट सिस्टम शुरू करना चाहिए। तीसरा, इन मानकों को अनिवार्य बताने को चुनौती देने के लिए डब्ल्यूटीओ प्रक्रिया का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा, अनुपालन संबंधी विषयों पर भारत सरकार द्वारा पहले से स्थापित व्यापार फोरमों के जरिए द्विपक्षीय रूप से और अधिक गहनता तथा रणनीतिक रूप से चर्चा करनी चाहिए। अन्त में, मानकों पर खरा उतरने के लिए घरेलू क्षमता में लैब, बेहतर विज्ञान जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयरों के जरिए सुधार लाना चाहिए तथा जागरूकता बढ़ाते हुए सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का एक डेटाबेस तैयार करना चाहिए।

भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले पांच वर्षों में कई अहम पड़ावों से गुजरी है। भारत सरकार ने समावेशी विकास सुनिश्चित करने, व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए तथा कृषि और औद्योगिक विकास के लिए कई सुधारात्मक एवं निर्णायक कदम उठाए हैं। विकास की गति बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार की सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय बजट 2019–20 में मुख्य रूप से जनता की महत्त्वाकांक्षाएं पूरी करने के रोडमैप पर ध्यान केंद्रित किया गया। जीडीपी वृद्धि को बढ़ने की उम्मीदों के बीच, सरकार ने राजकोषीय संतुलन बनाए रखते हुए बुनियादी ढांचागत क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, रोजगार सृजन को गति प्रदान करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहायता देने सहित भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का ब्लूप्रिंट रखा।

सरकार के इस विजन के अनुरूप, निवेश आधारित वृद्धि इस वर्ष के बजट की केंद्रीय थीम रही। इसमें देश के बुनियादी ढांचागत क्षेत्र तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा नवोद्यमों को सहायता प्रदान करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बैंकिंग जगत के पुनरुद्धार एवं कार्बन फुटप्रिंट घटाने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने जैसी बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया। चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए इंडिया इंक के साथ मिलकर काम करना इस बजट के सबसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं में से एक रहा।

केंद्रीय बजट 2019–20 में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं

- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था:** ग्रामीण विकास के लिए समग्र आबंटन में बढ़ोत्तरी की गई है। स्वयं-सहायता समूहों के लिए ब्याज अनुदान कार्यक्रम का विस्तार किया गया। महिला स्वयं-सहायता समूहों के लिए 5000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा और 1 लाख रुपये तक के ऋण की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 75,000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। राष्ट्रीय पेयजल मिशन के लिए आबंटन 5,500 करोड़ रुपये लगभग दोगुना बढ़ाकर 10,001 करोड़ रुपये किया गया है।
- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा नवोद्यम:** इनके लिए नई भुगतान व्यवस्था शुरू की गई है। जीएसटी रजिस्टर्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए 2% का ब्याज अनुदान; नवोद्यमों के लिए निवेशक पहचान का ई-सत्यापन उपलब्ध होगा; नवोद्यमों के शेयर प्रीमियमों के वैल्यूएशन में जांच के स्तरों को भी कम किया जाएगा।
- **बैंकिंग, एनबीएफसी और बीमा:** 70,000 करोड़ रुपये के बैंकिंग पुनर्पूंजीकरण की घोषणा की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में निवेश करने के लिए 10% तक की पहली हानि पर आंशिक ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी। डिबेंचर रिडेंप्शन रिजर्व के नियम संशोधित किए गए; आवास वित्त में विनियामकीय शक्ति को एनएचबी से आरबीआई को प्रदान कर आरबीआई का विनियामकीय प्राधिकार मजबूत किया गया तथा बीमा मध्यवर्ती संस्थाओं में 100% एफडीआई की घोषणा की गई।
- **मेक इन इंडिया:** आयकर अधिनियम की धारा 35डी के अंतर्गत निवेश संबंधी आयकर में छूट तथा अन्य कर लाभ प्रदान कर उभरते हुए तथा उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। कच्चे माल के आयातों पर सीमा शुल्क घटाया गया और कुछ वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाया गया, ताकि उच्चतर घरेलू मूल्य वर्धन किया जा सके और पेट्रोरसायन, विद्युत, स्टील, ऑटो पुर्जे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स (एसी जैसी घरेलू वस्तुओं सहित) जैसे क्षेत्रों में आयात निर्भरता कम की जा सके।
- **पूँजी बाजार:** ढांचागत क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए पूँजी के स्रोत बढ़ाने के उद्देश्य से पूँजीगत ऋण गारंटी संवर्धन निगम की स्थापना की जाएगी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों और इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्टों द्वारा जारी लिस्टेड ऋण प्रतिभूतियों को सब्सक्राइब करने की अनुमति दे दी गई है। वर्तमान न्यूनतम शेयरधारिता नियम 25% से बढ़ाकर 35% कर दिए गए हैं तथा सामाजिक उद्यमियों के लिए सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा है।

चुनिंदा क्षेत्रों पर प्रभाव

कृषि तथा संबंधित क्षेत्र समग्र प्रभाव: सकारात्मक 	• फसल बीमा योजना, सिंचाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य, खेती आदि के लिए आवंटन बढ़ाने का इस क्षेत्र पर सकारात्मक असर पड़ेगा। • पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड की योजना (स्फूर्ति) के अंतर्गत वर्ष 2019–20 के दौरान 100 नए क्लस्टरों की स्थापना से बेंत और शहद जैसे क्षेत्रों से 50,000 लोग आर्थिक श्रृंखला का हिस्सा बनेंगे। • प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत से मत्स्य क्षेत्र में वैल्यू चेन की खामियों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
ऑटोमोटिव तथा संबंधित क्षेत्र समग्र प्रभाव: तटस्थ 	• इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने के लिए ऋण पर देय ब्याज पर आयकर कटौती में अतिरिक्त छूट, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जीएसटी में कटौती तथा इलेक्ट्रॉनिक वाहन पुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क को घटाकर शून्य करने और लिथियम स्टोरेज बैटरियों जैसे क्षेत्रों में बड़े विनिर्माण संयंत्रों के लिए कर प्रोत्साहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। • इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के अलावा ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव पड़ने के आसार नहीं हैं।
बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा समग्र प्रभाव: सकारात्मक 	• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की तरलता में सुधार लाने पर फोकस करने और आरबीआई के बेहतर नियामकीय पर्यवेक्षण से इस क्षेत्र पर सकारात्मक असर होने की उम्मीद है। • बीमा मध्यस्थ कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में नरमी बरतने से बीमा कंपनियों के लिए वितरण चैनलों को विस्तार मिलेगा; विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों की शाखाओं के लिए वांछित अपेक्षाओं को कम करने से इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में सुधार आएगा।
बुनियादी ढांचागत क्षेत्र समग्र प्रभाव: सकारात्मक 	• सड़कों और रेलवे के लिए उच्चतर बजट आवंटन बना रहा; नागरिक उड्डयन के लिए आबंटन में भी पिछले वर्ष के मुकाबले 42% की बढ़ोत्तरी की गई। • वर्ष 2030 तक रेलवे के बुनियादी ढांचागत विकास के लिए 50 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश में तेजी लाने के लिए निजी सार्वजनिक भागीदारी प्रमुख रणनीति होगी। • सरकार की वर्तमान राजकोषीय स्थिति को देखते हुए बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में अगले पांच वर्षों के लिए प्रति वर्ष लगभग 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगभग 60% के निजी निवेश की आवश्यकता होगी। • तथापि, सड़क और बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में सेस में बढ़ोत्तरी के चलते बजट आबंटन कुछ हद तक बढ़ाने की जरूरत होगी।

6 कृषि और कृषि मशीनीकरण में भारत–अफ्रीका साझेदारी

संयुक्त राष्ट्र अन्य सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के साथ-साथ 2030 तक हर तरह की भुखमरी और कुपोषण को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। दुनिया में कुपोषितों की संख्या लगभग 795 मिलियन है। अगर 2050 तक 9 अरब की अनुमानित आबादी में से एक चौथाई भी अफ्रीका में रहती है तो हालात और बुरे हो सकते हैं, क्योंकि यह वह क्षेत्र है, जो कृषि क्षेत्र में उत्पादकता संबंधी बाधाओं का सामना कर रहा है। मैककिन्से के विश्लेषण से पता चलता है कि अफ्रीका में दो से तीन गुना अधिक अनाज की पैदावार हो सकती है, जिससे वैश्विक अनाज उत्पादन में 20% प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो सकती है।

कृषि उत्पादन का संक्षिप्त विवरण: भारत और अफ्रीका

भारत

- भारत में 2017-18 में 284.8 एमटी खाद्यान्न उत्पादन दर्ज किया गया, जो भारतीय कृषि के लिए अब तक का सबसे अधिक उत्पादन रहा।
- भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए 2013-14 से 2017-18 के दौरान 2% की एएजीआर दर्ज की गई।
- भारत के प्रमुख कृषि उत्पादों में अन्य के साथ-साथ गन्ना, चावल, गेहूं, आलू शामिल हैं।
- 2017 में अकेले गन्ना ही कुल भारतीय कृषि उत्पादन का 30% रहा।
- भारत में 2016 में 156.4 मिलियन हेक्यटेयर कृषि योग्य भूमि रही, जो दुनिया में सर्वाधिक है।
- किन्तु भारत में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि 0.118 हेक्टेयर रही, और भारत दुनिया के शीर्ष 100 देशों की संबंधित सूची में भी स्थान नहीं बना पाया।

अफ्रीका

- दुनिया की आधी से अधिक उपजाऊ किन्तु अप्रयुक्त भूमि अफ्रीका में ही है।
- कुछ अफ्रीकी देशों में कुल भूमि के % के रूप में कृषि भूमि का प्रतिशत अधिक है। इनमें दक्षिण अफ्रीका (79.8%), बुरुंडी (79.2%), नाइजीरिया (77.7%), लेसोथो (77.6%), इरिट्रिया (75.2%) शामिल हैं।
- कसावा (60.9%), जमीकंद (97.2%), शक्कर कंद (24.6%), ज्वार (47.3%), केला (60.1%) जैसे कृषि उत्पादों का योगदान वैश्विक उत्पादन में दोहरे अंकों में है।
- दुनिया में सबसे अधिक कृषि योग्य बिन जोती गई भूमि अफ्रीका में है, अधिकांश खेत 2 हेक्टेयर से कम के हैं।
- उप-सहारा अफ्रीका में कुल उत्पादन के औसतन 30% की कटाई के बाद क्षति हो जाती है। यानी इस क्षेत्र को प्रति वर्ष 4 अरब यूएस डॉलर की क्षति होती है।

कृषि उन्मुखीकरण सूचकांक

सरकारी खर्चों के लिए कृषि उन्मुखीकरण सूचकांक (एओआई) कृषि पर केंद्र सरकार के खर्च और जीडीपी में कृषि क्षेत्र के योगदान की तुलनात्मक तस्वीर पेश करता है। यदि यह सूचकांक 1 से कम है तो यह कृषि क्षेत्र के अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए केंद्र सरकार के न्यून योगदान को दर्शाता है। यदि यह सूचकांक 1 से अधिक है तो यह कृषि क्षेत्र के अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए केंद्र सरकार के उच्चतर योगदान को दर्शाता है। यह देखा जा सकता है कि एओआई में वैश्विक रूप से गिरावट आई है। 2001 में यह 0.42 था, जो 2017 में गिरकर 0.26 हो गया। यथा 2017 में उत्तर अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका क्षेत्रों का एओआई 0.12 रहा, वहीं मध्य अफ्रीका का एओआई 0.24, पूर्व अफ्रीका का 0.15 और दक्षिण अफ्रीका का 0.74 रहा। जाहिर है, अफ्रीका जैसे क्षेत्र में सरकारी स्तर पर कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जहां निजी निवेश कम है।

भारत–अफ्रीका कृषि व्यापार[1]

भारत-अफ्रीका कृषि व्यापार 2018 में 5.4 अरब यूएस डॉलर रहा, जो 2014 में 4.8 अरब यूएस डॉलर का था। दिलचस्प है कि अफ्रीका के साथ भारत का व्यापार तो लगातार सरप्लस रहा है, किन्तु इसका मूल्य पिछले पांच वर्षों से लगातार गिर रहा है और यह 2014 के 1.4 अरब यूएस डॉलर से गिरकर 2018 में 0.6 बिलियन यूएस डॉलर का रह गया है। वहीं, भारत द्वारा अफ्रीका से कृषि क्षेत्र में आयात 2014 में 1.7 अरब यूएस डॉलर का था, जो बढ़कर 2.4 अरब यूएस डॉलर का हो गया और इसमें 8.6% से अधिक की उल्लेखनीय एएजीआर दर्ज की गई।

भारत द्वारा अफ्रीका से कृषि क्षेत्र में आयातित उत्पादों में लगभग 97% हिस्सा शीर्ष पांच उत्पादों का ही है। मुख्य उत्पादों में फल और मेवा (66.2%); तिलहन और तैलोत्पादकी फल (10.2%); खाद्य वनस्पति और कुछ जमीकंद (10%); कॉफी, चाय, माते और मसाले (7.8); तथा कोकोआ और कोकोआ उत्पाद (2.6%) शामिल रहे।

अफ्रीका के कुल निर्यातों में 2018 में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 10% रहा। वर्ष 2018 में अफ्रीका से कृषि क्षेत्र में उत्पादों का निर्यात 48.4 अरब यूएस डॉलर का दर्ज किया गया, जो 2014 में 40.7 अरब यूएस डॉलर का था।

वर्ष 2018 में अफ्रीका द्वारा कृषि क्षेत्र में 63.9 अरब यूएस डॉलर का आयात किया गया, जो 2014 के 66.6 अरब यूएस डॉलर का था।

[1] एचएस कोड 06-23 लिए गए हैं

अफ्रीका द्वारा 2018 में किए गए कुल आयातों में कृषि उत्पादों का हिस्सा 11.1% रहा। अफ्रीका को अपनी एक अरब से ज्यादा की आबादी के भरण–पोषण के लिए बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है और इसकी मुख्य वजह कृषि योग्य भूमि का उपयोग न होना तथा मौजूदा कृषि व्यवस्था का मशीनीकरण न होना है।

वैश्विक निर्यात बाजार में अनाज, चीनी और मिठाई जैसे उत्पादों, पशु चारा, कॉफी, चाय और तैलोत्पादकी फल, विभिन्न अनाज, बीजों और फलों के वैश्विक निर्यात बाजार में भारत का उल्लेखनीय हिस्सा है और अफ्रीका भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत के साथ अपने व्यापार को बढ़ा सकता है।

कृषि मशीनरी में व्यापार[2]

कृषि मशीनरी में भारत का व्यापार 2018 में 2039.5 मिलियन यूएस डॉलर का रहा, जो 2014 में 1810.5 मिलियन यूएस डॉलर का था। भारत ने पिछले पांच वर्षों में कृषि मशीनरी के व्यापार में अच्छा सरप्लस बनाए रखा है और 2018 में 794.6 मिलियन यूएस डॉलर का रहा।

यद्यपि समग्र रूप में अफ्रीका के साथ भारत का व्यापार कम हुआ है, किन्तु जब कृषि मशीनरी की बात आती है तो यह सरप्लस हो जाता है। पिछले एक दशक में 2009 से 2018 के दौरान अफ्रीका को भारत के निर्यातों में तीन गुना बढ़ोत्तरी हुई है। यह 104.9 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 323.5 मिलियन यूएस डॉलर का हो गया, जिसमें 17.7% की एएजीआर दर्ज की गई।

अफ्रीका द्वारा 2018 में कृषि मशीनरी में कुल व्यापार 6.1 अरब यूएस डॉलर दर्ज किया गया, जो 2014 के 6.9 अरब यूएस डॉलर से कुछ कम रहा। तथापि, 2017 में इस क्षेत्र में व्यापार में कुछ सुधार के संकेत मिले और यह 2016 की तुलना में 9.5% की दर से बढ़ा। वहीं, 2017 की तुलना में 2018 में इसमें 12.9% की वृद्धि दर्ज की गई।

ये आंकड़े कृषि मशीनरी के लिए अफ्रीका के बड़े बाजार की ओर संकेत करते हैं, जिसमें भारत उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए अफ्रीका के साथ मिलकर काम कर सकता है। वर्ष 2018 में विश्व के कुल मशीनरी आयातों में 5% हिस्सा अकेले अफ्रीका का ही रहा। अतः भारत के लिए इस बाजार में अच्छी संभावनाएं हैं।

कृषि और कृषि प्रसंस्करण में सहयोग की संभावनाएं

चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है और अफ्रीका के साथ ऐतिहासिक रूप से हमारे मधुर संबंध रहे हैं। अतः भारत कृषि वैल्यू चेन में अपने अनुभव अफ्रीका के साथ साझा कर सकता है और अफ्रीका को कृषि उत्पादों का नया निर्यातक बनने में मदद कर सकता है।

कृषि क्षेत्र में भारत हरित क्रांति से लेकर कॉन्ट्रैक्ट खेती, ड्रिप सिंचाई, कृषि बाजारों, सैटेलाइट खेती, रोबोटिक्स, संस्थागत सहायता और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में अफ्रीका के साथ अपने अनुभव साझा कर सकता है। इसके अतिरिक्त, कृषि मशीनीकरण में सहयोग करने के अतिरिक्त, कृषि उपकरणों के व्यापार में विशाखन, नए बिजनेस मॉडल, निजी क्षेत्र के लिए अनुकूल परिवेश का निर्माण कराने में सहायता करने तथा अनुसंधान एवं विकास में सहयोग देने जैसे फैक्टरों पर भी अफ्रीका की सरकारें भारतीय संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर सकती हैं। पारस्परिक लाभ के लिए भारत–अफ्रीका कृषि फंड भी स्थापित किया जा सकता है।

छठे अफ्रीका–भारत भागीदारी दिवस पर एक्ज़िम बैंक के शोध अध्ययन का विमोचन

मलाबो, इक्विटोरियल गिनी में आयोजित अफ्रीकी विकास समूह की वार्षिक बैठकों से संबंधित कार्यक्रम में आयोजित छठे भारत–अफ्रीका भागीदारी दिवस के अवसर पर एक्ज़िम बैंक के शोध अध्ययन 'कृषि और कृषि यंत्रीकरण में भारत–अफ्रीका भागीदारी' का विमोचन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (डीईए) श्री प्रशांत गोयल द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम 13 जून, 2019 को आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य अफ्रीका में क्षेत्रीय एकीकरण से जुड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भारत के अनुभवों को साझा करना था।

अध्ययन में अफ्रीका और भारत के बीच सहयोग के उन संभावित क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है जो दोनों क्षेत्रों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। एक समय में खाद्यान्नों के आयातक भारत के पास आज खाद्यान्नों का निवल अधिशेष है। लगभग 50 साल पहले शुरू हुई हरित क्रांति के बाद से भारत में कृषि क्षेत्र में कई कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ ही संस्थागत और प्रौद्योगिकीय सुदृढ़ीकरण हुआ है, जिसे अफ्रीकी संदर्भ में दोहराया जा सकता है।

इस कार्यक्रम में अफ्रीका में क्षेत्रीय एकीकरण की गति को तेज करने संबंधी विषय पर एक परिचर्चा भी आयोजित की गई, जिसमें भारतीय और अफ्रीकी देशों के वक्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में अफ्रीकी देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों, भारत और अफ्रीका की विकास वित्त संस्थाओं, बैंकों और कंपनियों के सीईओ सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

[2] एचएस 6 डिजिट लेवल की 53 वस्तुएं

भारतीय निर्यात–आयात बैंक ने लद्दाख, जम्मू–कश्मीर की महिला पश्मीना बुनकरों को दिया सहयोग

एक्ज़िम बैंक अपने ग्रासरूट उद्यम विकास (ग्रिड) कार्यक्रम और मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के जरिए ग्रासरूट पहलों तथा निर्यात उन्मुख नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी को वित्तीय और सलाहकारी दोनों प्रकार की सहायता देता रहा है। उसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय सूक्ष्म उद्यमों की परिचालनात्मक क्षमता को बढ़ाने, उनके उत्पादों का उच्चतर मूल्य वर्धन करने तथा उन्हें नए बाजारों तक पहुंचाने के साथ–साथ इन उद्यमों की निर्यात क्षमताएं और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है। इसके लिए बैंक कौशल विकास, उत्पाद विकास आदि में सहयोग देता है और उनके उत्पादों के लिए निर्यात बाजार प्रमाणीकरण दिलाने में भी मदद करता है।

इस संदर्भ में, एक्ज़िम बैंक भारत की पारंपरिक कलाओं के संरक्षण और शिल्पकारों को आजीविका का स्थायी माध्यम प्रदान करने और आजीविका बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य से देश के अलग–अलग हिस्सों के ग्रासरूट उद्यमों और शिल्पकारों को उत्पाद विकास, डिजाइन, पैकेजिंग आदि में सहायता प्रदान करता रहा है। बैंक ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के जरिए नई पीढ़ी के दस्तकारों को अपनी पैतृक कला को सीखने और उसके जरिए व्यवसाय का मॉडल खड़ा करने के लिए प्रेरित करने तथा देश की विभिन्न कलाओं को देश–विदेश के विभिन्न मंचों पर उनका उचित सम्मान दिलाने में भी सहयोग किया है।

बैंक ने 'लूम्स ऑफ लद्दाख वीमेन्स को–ऑपरेटिव' (एलएलडब्ल्यूसी) के साथ मिलकर इस संगठन के बुनाई–कताई करने वाले कारीगरों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी में कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस क्लस्टर विकास कार्यक्रम का उद्देश्य पश्मीना बुनकरों का कौशल विकास और डिजाइन विकास करना था, ताकि उन्हें अपने उत्पादों के लिए नए बाजार आसानी से मिल सकें। यह कार्यशाला गुरु–शिष्य परंपरा पर आधारित थी। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी के दस्तकारों को पश्मीना ऊन से बुनाई की इस प्राचीन कला में पारंगत करना और जिले के सुदूर गांवों की बेरोजगार महिलाओं को साथ लाते हुए उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध कराना था। इस कार्यक्रम में कुल 42 बुनकरों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने पश्मीना, भेड़, याक और बैक्ट्रियन ऊंट से मिलने वाली ऊन से दस्तानों से लेकर टोपियां, हुड, बंदाना, स्कार्फ और स्टोल जैसे विभिन्न उत्पाद बनाए।

इस कौशल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और सुदूर ग्रामीण महिलाओं को पश्मीना की बुनाई में निपुण बनाना था, जिससे एलएलडब्ल्यूसी का नेटवर्क समूचे लद्दाख में फैल सके। मध्य प्रदेश के हैंडलूम स्कूल ऑफ माहेश्वर से पश्मीना, याक और मेरिनो भेड़ों से मिलने वाली ऊन की उन्नत बुनाई में प्रशिक्षित दो बुनकरों से इस कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिलाया गया। उन्हें आठ फ्रेम वाली छोटी लूम पर प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वे मफलर बनाने, उच्च गुणवत्ता वाले महंगे उत्पाद बनाने और उन्नत बुनाई यार्डेज संबंधी गणना में सक्षम हो सके। इन दो मास्टर प्रशिक्षकों ने सबसे पुराने मास्टर प्रशिक्षक और एक डिजाइनर के साथ मिलकर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया, जिसमें एलएलडब्ल्यूसी के सात क्लस्टरों से प्रतिभागिता की गई।

उन्नत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम – एलएलडब्ल्यूसी

उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति तक कुल 42 सैंपल प्रोटोटाइप बनाए गए और प्रत्येक केंद्र पर 6 बुनकरों को प्रशिक्षित किया गया। बैंक ने लद्दाख क्षेत्र के मोटिफ पैटर्न के लिए कॉपीराइट पेटेंट दिलाने में भी सहायता की, जिसका नाम 'लद्दाखी पश्मीना शॉल' प्रस्तावित किया गया है। यह मल्टी शटल 60 वाइड लूम पर बना उत्पाद है और एलएलडब्ल्यूसी द्वारा यार्डेज पर आधारित है।

पश्मीना उत्पाद

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से न केवल लद्दाख बुनकर क्लस्टर को लाभ मिला, जिसे अपने लिए एक ब्रांड नाम बनाने और इसे विकसित करने के लिए चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि नई पीढ़ी के बुनकरों को भी तैयार करने में मदद मिली, जो अपनी इस अनूठी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। यह बैंक के ग्रिड कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक यानी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में अपना योगदान देने के उद्देश्य को हासिल करने की दिशा में किया गया एक प्रयास है।

छूछोट गांव में काम करतीं महिलाएं

बुनाई के लिए कच्चा माल तैयार करतीं महिलाएं

एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है, जो उन देशों के क्रेताओं को भारत से आस्थगित भुगतान शर्तों पर विकासपरक तथा बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं। एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इनके अंतर्गत एक्ज़िम बैंक माल के शिपमेंट पर भारतीय निर्यातक को संविदा मूल्य के 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करता है, बशर्ते कि कुल संविदा मूल्य के कम से कम 75 प्रतिशत के माल एवं सेवाओं का शिपमेंट भारत से किया गया हो। ऋण-व्यवस्थाओं के जरिए उभरते बाजारों में भारत की परियोजना निष्पादन क्षमता के प्रदर्शन में भी मदद मिली है। हाल के वर्षों में ऋण-व्यवस्थाओं ने गति पकड़ी है। विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशियानिया और सीआईएस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं। बैंक द्वारा अब तक अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिनिया और सीआईएस क्षेत्रों के 62 देशों को 24.66 अरब यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता के साथ 248 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं, जो भारत से निर्यातों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार ऋण-व्यवस्थाएं विकासशील देशों में भारत से परियोजनाओं, माल और सेवाओं के निर्यात के संवर्द्धन और सुगमीकरण के लिए प्रभावी साधन हैं।

एक्ज़िम बैंक ने अप्रैल-जून 2019 के दौरान भारत सरकार की ओर से निम्नलिखित तीन ऋण-व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर किए:

(i) घाना सरकार को येंदी में पेयजल प्रणाली के जीर्णोद्धार और उन्नयन हेतु 30 मिलियन यूएस डॉलर तथा कृषि यंत्रीकरण सेवा केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए 150 मिलियन यूएस डॉलर की दो ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गईं। उक्त ऋण-व्यवस्थाओं सहित एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से घाना सरकार को अब तक कुल 388.26 मिलियन यूएस डॉलर की नौ ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। इन ऋण-व्यवस्थाओं के जरिए घाना में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने वाली परियोजनाओं, कृषि और परिवहन परियोजनाओं, राष्ट्रपति भवन के निर्माण, रेलवे कॉरीडोर, कृषि प्रसंस्करण संयंत्र, विदेश नीति प्रशिक्षण संस्थान, मत्स्य प्रसंस्करण संयंत्र, अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना, चीनी संयंत्र और गन्ना विकास और सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहयोग प्रदान किया गया है।

(ii) बांग्लादेश सरकार को रक्षा संबंधी खरीद के लिए 500 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। उक्त ऋण-व्यवस्था सहित एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से बांग्लादेश सरकार को अब तक कुल 7,862 मिलियन यूएस डॉलर की चार ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। इन ऋण-व्यवस्थाओं के जरिए बांग्लादेश में रेलवे के बुनियादी ढांचे, ड्रेजिंग, पुलों के निर्माण, बसों, लोकोमोटिव और रेल के डिब्बों की खरीद तथा विभिन्न सामाजिक एवं बुनियादी ढांचागत विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए सहयोग प्रदान किया गया है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क कीजिए

सुश्री मीना वर्मा,
महाप्रबंधक,
भारतीय निर्यात-आयात बैंक,
ऑफिस ब्लॉक, टॉवर 1, 7वीं मंज़िल
एड्जेसेंट रिंग रोड
किदवई नगर (पूर्व)
नई दिल्ली - 110023
टेलीफोन: (011) 24607700
ई-मेल : eximloc@eximbankindia.in

सफलता की कहानी: कोत दि'वार

कोत दि'वार में महात्मा गांधी आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण के वित्तपोषण के लिए कोत दि'वार सरकार को 25.50 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। 20 मिलियन यूएस डॉलर की इस परियोजना का उद्घाटन 27 जून, 2019 को किया गया था। परियोजना शापूरजी पाल्लोनजी एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया गया। इसके कार्यों में डिजाइन, वास्तु तथा तकनीकी अध्ययन, आईटी उद्यमों के लिए भवन का निर्माण और कैंपस के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण शामिल था। कंप्यूटर असेंबली प्लांट, डीएनए लैब, सैटेलाइट अर्थ स्टेशन,

ऑडियो-वीडियो, टेलीकॉम लैब, जनरेटर और डाटा स्टोरेज नेटवर्क के लिए उपकरणों की आपूर्ति और उनका इंस्टॉलेशन यूनाइटेड टेलोकॉम लिमिटेड द्वारा किया गया। आईटी और बायोटेक्नोलॉजी के लिए अलग से मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफटीजेड) से अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए ग्रैंड बैसम, कोत दि'वार स्थित एफटीजेड से संचालित कंपनियों को कर में छूट जैसे लाभ मिलेंगे।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में एक्ज़िम बैंक का कर पश्चात लाभ ₹ 82 करोड़ रहा

भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) के प्रबंध निदेशक श्री डेविड रस्कीना और उप प्रबंध निदेशक श्री देबाशिस मल्लिक ने गुरुवार, 30 मई, 2019 को मुंबई में आयोजित एक प्रेस वार्ता में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बैंक के वित्तीय परिणामों की घोषणा की। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बैंक के वित्तीय परिणामों की प्रमुख विशिष्टताएं निम्नलिखित अनुसार रहीं:

वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

ऋण पोर्टफोलियो	93,617
गैर–निधिक पोर्टफोलियो	14,096
परिचालन लाभ	2,068
नेटवर्थ	14,674
कर पश्चात लाभ	82
भारत सरकार को अंतरित लाभ की शेष राशि	8.17
प्रति कर्मचारी व्यवसाय	571
प्रावधान कवरेज अनुपात	84.72%
जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात	19.07%
निवल अनर्जक आस्तियां (एनपीए)	2.44%

ऋण–व्यवस्थाएं: वित्तीय वर्ष 2017–19 के दौरान बैंक द्वारा 2.31 बिलियन यूएस डॉलर की 18 ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की गईं। यथा 31 मार्च, 2019 को बैंक द्वारा अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और सीआईएस क्षेत्रों में 24.28 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता के साथ 63 देशों को 246 ऋण–व्यवस्थाएं दी गई हैं।

परियोजना निर्यात: बैंक ने भारत से परियोजना निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए अपनी वाणिज्यिक ऋण योजना के अंतर्गत कुल ₹ 4,895 करोड़ के ऋण और गारंटियां जारी कीं। इसके अंतर्गत कुल ₹ 23,500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स को सहयोग प्रदान किया गया। बैंक ने थाईलैंड, यूएई, यूएसए जैसे देशों और अफ्रीका के 14 देशों में परियोजना निर्यातों को सहयोग प्रदान किया।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण (बीसी–एनईआईए): यथा 31 मार्च, 2019 को एक्ज़िम बैंक ने बीसी–एनईआईए के अंतर्गत 21 परियोजनाओं के लिए 2.10 बिलियन यूएस डॉलर के क्रेता ऋण की मंजूरी दी है। कुछ प्रमुख परियोजनाओं में श्रीलंका में जल प्रशोधन तथा वितरण परियोजना; कैमरून, इथियोपिया, मौरिटानिया, सेनेगल एवं जाम्बिया में ट्रांसमिशन लाइन परियोजना; घाना में रेलवे लाइन परियोजना; मालदीव एवं जाम्बिया में सड़क परियोजना तथा सूरीनाम में सिंचाई परियोजना शामिल हैं। बैंक ने कई प्रमुख भारतीय निर्यातकों की ओर से निष्पादित की जाने वाली 43 परियोजनाओं को 5.32 बिलियन यूएस डॉलर की सहायता प्रदान करने हेतु सिद्धांततः सहमति भी दी है।

विदेशी निवेश वित्त: वर्ष 2018–19 के दौरान, भारतीय कंपनियों को 8 देशों में उनके विदेशी निवेश के आंशिक वित्तपोषण के लिए कुल ₹1,136 करोड़ की निधिक तथा गैर–निधिक सहायता प्रदान की गई। एक्ज़िम बैंक अब तक 78 देशों में 467 कंपनियों द्वारा 621 उद्यमों की स्थापना के लिए कुल ₹58,427 करोड़ की सहायता प्रदान कर चुका है।

वर्ष 2018–19 के दौरान बैंक का कर पश्चात लाभ (पीएटी) ₹ 82 करोड़ रहा।

छठे अफ्रीका–भारत भागीदार दिवस पर क्षेत्रीय एकीकरण पर चर्चा

एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार और अफ्रीकी विकास बैंक के सहयोग से मलाबो, इक्विटोरियल गिनी में आयोजित अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) समूह की वार्षिक बैठक के दौरान 'अफ्रीका–भारत भागीदारी दिवस' का आयोजन किया। अफ्रीका–भारत भागीदारी दिवस का यह छठा आयोजन था। यह अब अफ्रीकी विकास बैंक समूह की वार्षिक बैठकों से जुड़े कार्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। इस वर्ष की थीम– 'अफ्रीका में क्षेत्रीय एकीकरण को गति प्रदान करना' रही।

अपने विशाल क्षेत्र को एकीकृत करने की दिशा में भारत के प्रयासों के साथ ही लैंडमार्क परियोजनाओं के माध्यम से पड़ोसियों से संपर्क विकसित करने संबंधी भारत के अनुभव अफ्रीका के संदर्भ में भी उपयोगी हो सकते हैं। अतः एक विकासशील देश के रूप में भारत के अनुभव अफ्रीका के लिए उपयुक्त होने के साथ–साथ अफ्रीका–भारत की भागीदारी को एक नए धरातल पर ले जा सकते हैं, जहां दोनों क्षेत्र अपनी–अपनी चुनौतियों और अवसरों को समझते हुए सहयोग कर सकते हैं।

अपने मुख्य वक्तव्य में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव (डीईए) श्री प्रशांत गोयल ने भारतीय परियोजनाओं की भूमिका और सफलता के कई उदाहरण दिए। ये उदाहरण मुख्य रूप से तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, सड़क नेटवर्क को एकीकृत करने, क्षेत्रीय पॉवर ग्रिडों को एक राष्ट्रीय ग्रिड के अंतर्गत लाने, भारत–बांग्लादेश जल संधि को सफलतापूर्वक लागू करने के अलावा चार राष्ट्रों बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ वाहनों की आवाजाही संबंधी संधि और म्यांमार के साथ मल्टीमॉडल परिवहन प्रणाली की शुरुआत पर हस्ताक्षर करने से संबंधित थे।

इस अवसर पर श्री गोयल ने 'कृषि एवं कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में भारत–अफ्रीका साझेदारी' नामक भारतीय एक्ज़िम बैंक के एक अध्ययन का भी विमोचन किया।

व्यापार लागत में कटौती से भारत और लैक के बीच बढ़ सकता है 16 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का व्यापार: भारतीय एक्ज़िम बैंक और इंटर–अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक का संयुक्त अध्ययन

फिक्की तथा आई डी बी द्वारा 11 जून, 2019 को नई दिल्ली, भारत में 'भारत–लैक व्यापार एवं निवेश' पर एक उद्योग परिचर्चा सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के दौरान भारतीय निर्यात–आयात बैंक तथा इंटर–अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक द्वारा मिलकर किए गए शोध अध्ययन 'भारत और लैटिन अमेरिका के बीच संबंध– सुदृढ़ आर्थिक सहयोग के लिए नीतिगत विकल्प' का विमोचन श्री जी.वी. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव (लैक), भारत सरकार, विदेश मंत्रालय; श्री जेम्स स्क्रिवेन, सीईओ ऑफ आई डी बी इन्वेस्ट; तथा श्री देबाशिस मल्लिक, उप प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात–आयात बैंक द्वारा किया गया। इस अवसर पर फिक्की के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

यह अध्ययन भारत और लैक क्षेत्र दोनों के लिए व्यापार, निवेश और पारस्परिक सहयोग क्षेत्रों में मौजूद असीमित अवसरों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसमें यह रेखांकित किया गया है कि इन दोनों क्षेत्रों के बीच वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार केवल कुछ उत्पादों एवं कुछ देशों में ही केंद्रित है। तथा यह उल्लेख किया गया है कि दोनों देशों के बीच द्विक्षीय व्यापार 2018 में लगभग 40 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका है।

अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि लैक क्षेत्र और भारत के बीच वस्तुओं की व्यापार लागत एक बाधा है जिसे आर्थिक संबंधों और व्यापार लाभ को बढ़ाने के लिए कम करने की जरूरत है। व्यापार लागत टैरिफ, गैर–टैरिफ बाधाओं (एनटीबी) और परिवहन और लॉजिस्टिक मार्गों सहित अक्षमताओं के चलते है। यह अनुमान है कि मध्यम अवधि में व्यापार लागत में कमी के साथ भारत को लैक क्षेत्र का निर्यात 42 प्रतिशत बढ़ सकता है, जबकि लैक क्षेत्र को भारतीय निर्यात 46 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। वर्तमान मूल्य के संदर्भ में इसका मतलब है कि लैक क्षेत्र द्वारा निर्यातों में 7.6 बिलियन यूएस डॉलर और भारत द्वारा निर्यातों में 8.6 बिलियन यूएस डॉलर तक की वृद्धि हो सकती है।

पहली बार पश्चिम बंगाल में सजा एक्ज़िम बाज़ार – हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की अनूठी प्रदर्शनी

एक्ज़िम बैंक ने हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए सितंबर 2017 में एक्ज़िम बाज़ार नाम से इन उत्पादों की अनूठी प्रदर्शनी शुरू की थी। एक्ज़िम बैंक एक्ज़िम बाज़ार नाम की इस पहल के जरिए देशभर से ग्रासरूट उद्यमों और दस्तकारों को उनके उत्पादों को घरेलू और विदेशी बाजारों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए उनकी सहायता करने तथा आजीविका में सुधार लाने का प्रयास करता है। इस क्रम में चौथे एक्ज़िम बाज़ार का आयोजन 12-14 अप्रैल, 2019 के दौरान कोलकाता में किया गया।

प्रदर्शनी के दौरान ढोकरा कला, सांझी पेंटिंग, टेराकोटा की वस्तुएं, चेन्नापटना के खिलौने, फड़ और पिछवाई पेंटिंग, एप्लीक और कढ़ाई किए हुए टेक्सटाइल्स और गारमेंट, जूट के बैग और दरियां, पंजाबी जूतियां, जूते-चप्पल, इकत टेक्सटाइल्स, चमड़े की कठपुतली, घास से बनी टोकरियां, मधुबनी और पट्टचित्र पेंटिंग जैसे उच्च गुणवत्ता वाले हस्तनिर्मित उत्पादों की बिक्री की गई। इसमें बड़ी संख्या में लोग आए और प्रदर्शनी के दौरान दस्तकारों के उत्पादों की अच्छी बिक्री हुई। कई दस्तकारों को थोक में आगामी ऑर्डर भी मिले।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क कीजिए: grid@eximbankindia.in

एक्ज़िमिअस शिक्षण केंद्र की गतिविधियां

एक्ज़िम बैंक ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ मिलकर एडीबी द्वारा निधिक परियोजनाओं में व्यवसाय अवसरों पर एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार नई दिल्ली में 27 जून, 2019 को हुआ, जिसमें 100 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी जानकारियों के प्रसार तथा निर्यात क्षमता सृजन और विभिन्न भौगोलिक हिस्सों तक पहुंचने के उद्देश्य से एक्ज़िम बैंक ने वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है। इसे एक्ज़िम बैंक की मास्टर क्लास नाम दिया गया है। इस क्रम में पहली मास्टर क्लास 21 जून, 2019 को 'भारत से वस्तु निर्यातः संवाहक और वृद्धि की संभावनाएं' विषय पर आयोजित की गई और इसका संचालन एक्ज़िम बैंक की अर्थशास्त्री सुश्री जाह्नवी द्वारा किया गया। वेबिनार को देश-विदेश से 100 से अधिक लोगों ने देखा-सुना। वक्ता के सत्र के बाद प्रश्नोत्तर सत्र भी रखा गया।

अप्रैल-जून 2019 तिमाही के दौरान बैंक ने अप्रैल 2019 में कोलकाता में आयोजित खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी सम्मेलन के लिए इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ साझेदारी की। एक्ज़िम बैंक ने एसोचैम के साथ मिलकर मई 2019 में मुंबई में 'वस्तु निर्यात स्पर्धात्मकता का संवर्धन' विषय पर एक सत्र का आयोजन किया। एक्ज़िम बैंक ने भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर अफ्रीका के साथ व्यापार विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का आयोजन जून 2019 में कोलकाता में किया गया।

एक्ज़िम बैंक अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निर्यात क्षमता सृजन से संबंधित विषयों पर देशभर में विभिन्न सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन करता रहता है।

अपने क्षेत्र में होने वाले आगामी कार्यक्रमों की जानकारी के लिए कृपया देखें:

http://www.eximbankindia.in/upcoming-events

एक्ज़िम बैंक का पूर्वानुमान, वित्तीय वर्ष 2020 की पहली तिमाही में भारत के वस्तु तथा गैर तेल निर्यातों में होगी सकारात्मक वृद्धि

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून, 2019 के दौरान, पिछले वर्ष की इसी तिमाही के मुकाबले भारत के कुल वस्तु निर्यात के 81.9 अरब यूएस डॉलर से 84.0 अरब यूएस डॉलर (2.5% प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि) तथा गैर-तेल निर्यातों के 70.1 अरब यूएस डॉलर से 73.0 अरब यूएस डॉलर (4.2 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि) होने का पूर्वानुमान लगाया है। यह पूर्वानुमान एक्ज़िम बैंक के एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स (ईएलआई) मॉडल पर आधारित है। भारत के कुल वस्तु निर्यातों और गैर-तेल निर्यातों में वृद्धि के पूर्वानुमान हर तिमाही आधार पर संबंधित तिमाही के लिए जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च के पहले सप्ताह में जारी किए जाते हैं। जुलाई-सितंबर 2019 तिमाही के लिए भारत के निर्यातों में वृद्धि का अगला पूर्वानुमान सितंबर 2019 के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा।

एक्ज़िम बैंक ने, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, ईएलआई मॉडल पर आधारित भारत के वस्तु निर्यातों को 331.8 अरब यूएस डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया था, जो 331.02 बिलियन यूएस डॉलर के आधिकारिक अनुमानों के अनुरूप है।

इस मॉडल तथा इससे प्राप्त पूर्वानुमान संबंधी परिणामों की समीक्षा विशेषज्ञों की एक स्थाई तकनीकी समिति द्वारा की गई है। इस समिति के सदस्यों में प्रोफेसर सैकत सिन्हा रॉय, प्रोफेसर एवं संयोजक, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज, अर्थशास्त्र विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता; डॉ. सरत धल, निदेशक, अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता; प्रोफेसर एन.आर. भानुमूर्ति, प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फायनेंस एंड पॉलिसी (एन आई पी एफ पी), नई दिल्ली तथा प्रोफेसर सी. वीरामणि, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च (आई जी आई डी आर), मुंबई शामिल हैं।

अपने शोध प्रयासों की कड़ी में एक्ज़िम बैंक भारत के निर्यातों का तिमाही आधार पर ट्रैक रखने तथा वृद्धि में पूर्वानुमान के लिए एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स (ई एल आई) तैयार करने हेतु विकसित यह इन-हाउस मॉडल है। यह इंडेक्स देश के निर्यातों पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न बाह्य एवं घरेलू कारकों को ध्यान में रखते हुए कुल वस्तु एवं गैर-तेल निर्यातों में तिमाही आधार पर वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में विकसित किया गया है।

12 बिम्सटेक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार

पृष्ठभूमि

बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) 1997 में गठित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। इसके सदस्य देश तटीय और बंगाल की खाड़ी से लगते क्षेत्रों में हैं और ये सब मिलकर क्षेत्रीय एकता की मिसाल पेश करते हैं। इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं – बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। वहीं, शेष दो सदस्य म्यांमार और थाईलैंड दक्षिणपूर्वी एशिया से हैं। बिम्सटेक की संयुक्त आबादी देखें तो यह लगभग 1.67 अरब है, जो विश्व की लगभग 22% आबादी है। इनका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2018 में 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर से अधिक रहा, जो वैश्विक जीडीपी का 4.3% है। अन्य क्षेत्रीय समूहों के विपरीत, बिम्सटेक क्षेत्र-संचालित सहकारी संगठन है, जो व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्यपालन, कृषि, जन-स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद पर वार, पर्यावरण, संस्कृति, जन-जन का जन-जन से संपर्क और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों पर काम करता है।

बिम्सटेक का रणनीतिक महत्त्व इसलिए भी है कि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच पुल का काम करता है और अंतःक्षेत्रीय व्यापार एवं सार्क तथा आसियान सदस्य देशों के बीच सहयोग के लिए एक मंच मुहैया करता है। पाकिस्तान के साथ सहमति न बन पाने के चलते सार्क के पीछे हटने से बिम्सटेक क्षेत्रीय एकीकरण और भारत तथा दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

बिम्सटेक देशों का कुल व्यापार

बिम्सटेक देशों के कुल व्यापार में पिछले एक दशक में 7.5% से ज्यादा की सीएजीआर दर्ज की गई। यह 2009 के 790.4 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर 2018 में 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का हो गया। बिम्सटेक देशों से 2018 में कुल निर्यात 646.1 अरब यूएस डॉलर और आयात 864.2 अरब यूएस डॉलर का रहा। बिम्सटेक के कुल व्यापार में 2018 में अकेले भारत का योगदान ही 54% का रहा। बिम्सटेक से कुल निर्यातों में 59% और आयातों में 54% योगदान भारत का रहा। इस क्षेत्र से व्यापार करने वाले अन्य प्रमुख देशों में थाईलैंड (बिम्सटेक के कुल व्यापार का 33.2%), बांग्लादेश (6.6%), म्यांमार (2.4%), और श्रीलंका (2.1%) का स्थान रहा। अंतः क्षेत्रीय व्यापार कुल व्यापार का 6% ही रहा, जो सदस्य देशों के बीच व्यापार की अपार संभावनाओं और सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के अवसरों को दर्शाता है।

बिम्सटेक मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्रेमवर्क करार पर 2004 में हस्ताक्षर हुए थे। किन्तु टैरिफ में कमी और टैरिफ हटाएं जाने के तरीकों, नकारात्मक सूची, मूल उत्पत्ति के नियमों के लिए मापदंड, विवाद निपटारे की प्रक्रिया, सुरक्षा के उपाय, सीमा शुल्क परिचालन और सेवाओं तथा निवेश संबंधी करारों पर वार्ता जैसे विषयों को लेकर आपसी सहमति के अभाव में इसे आज तक लागू नहीं किया जा सका है।

बिम्सटेक के साथ भारत का व्यापार

भारत और अन्य बिम्सटेक देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार के रुझान दर्शाते हैं कि दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार की कितनी संभावनाएं हैं और वाणिज्यिक संबंधों को किस तरह शिखर पर ले जाया जा सकता है। भारत और अन्य बिम्सटेक सदस्य देशों के बीच कुल व्यापार 2009 के 12.3 अरब यूएस डॉलर से तीन गुना बढ़कर 2018 में 37.9 अरब यूएस डॉलर हो गया। भारत से बिम्सटेक देशों को निर्यातों में भी चार गुना बढ़ोत्तरी हुई है। निर्यात 2009 के 7.3 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर 2018 में 27 अरब यूएस डॉलर हो गया। वहीं, बिम्सटेक क्षेत्र से भारत द्वारा आयातों में दोगुनी से अधिक बढ़ोत्तरी हुई और यह आयात 2009 के 5.1 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर 2018 में 11 अरब यूएस डॉलर का रहा।

भारत-बिम्सटेक व्यापार 2018 में भारत के कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 4.6% रहा। भारत से कुल निर्यातों का 8.3% निर्यात बिम्सटेक को रहा और भारत द्वारा कुल आयातों का 2.2% बिम्सटेक से रहा। बिम्सटेक देशों में थाईलैंड 2018 में 31.7% हिस्से के साथ भारत का प्रमुख व्यापार भागीदार रहा। वहीं, भारत से बिम्सटेक देशों द्वारा आयातों के कुल 32.5% हिस्से के साथ बांग्लादेश बिम्सटेक देशों में भारत से प्रमुख आयातक रहा। इसके बाद नेपाल (27%), श्रीलंका (17.3%) और थाईलैंड (16.2%) का स्थान रहा। बिम्सटेक से भारत के कुल आयातों का लगभग 70% हिस्सा थाईलैंड से रहा। इसके बाद 12% और 8.1% हिस्से के साथ क्रमशः श्रीलंका और बांग्लादेश का स्थान रहा।

भारत द्वारा बिम्सटेक देशों को प्रमुख रूप से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में खनिज ईंधन, तेल और उनके उत्पाद (14.4%), रेलवे और ट्रामवे के अतिरिक्त वाहन (10.3%), रूई (9.3%) और यांत्रिक उपकरण (8.2%) शामिल हैं। भारत द्वारा बिम्सटेक देशों से प्रमुख रूप से मशीनरी और यांत्रिक उपकरण (कुल आयातों का 13.2% हिस्सा), प्लास्टिक और वस्तुएं (9.7%), इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण (9%) तथा अकार्बनिक रसायन (6.7%) शामिल रहे।

भारत–बिम्सटेक संबंधः आगे की राह

भारत बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के आसपास संपर्क परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, क्योंकि इससे पूर्वोत्तर भारत के सातों राज्यों से निर्यातों की संभावनाएं बढ़ाने में मदद मिलेगी। म्यांमार का सितवे बंदरगाह भारत के अपने बंदरगाहों की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र के नजदीक है। इसके अतिरिक्त, बिम्सटेक के साथ भौतिक संपर्क के जरिए भारत को आसियान के संपर्क मास्टर प्लान 2025 के साथ एकीकृत होने में भी मदद मिलेगी। भारत द्वारा म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना और बिम्सटेक मोटर वाहन करार में पहले ही निवेश किया जा चुका है। बेहतर संपर्क परियोजनाओं के जरिए भारत को बिम्सटेक से व्यापार की अदोहित संभावनाओं को भुनाने में मदद मिलेगी।

सहयोग के 14 क्षेत्रों सहित बिम्सटेक का फोकस काफी विस्तृत है। बिम्सटेक को छोटे फोकस क्षेत्रों के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए और उन्हीं में कुशलतापूर्वक सहयोग करना चाहिए। चीन की अतिसक्रिय सदस्यता के साथ बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार (बीसीआईएम) के रूप में एक अन्य उप क्षेत्रीय पहल के गठन ने बिम्सटेक की संभावनाओं के संबंध में संदेह पैदा करने का काम किया है। इस समूह में सबसे बड़ा और सबसे विकसित देश होने के नाते इसे आगे ले जाने का जिम्मा भी भारत के कंधों पर ही है।

थाई बात

कभी 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के केंद्र में रही यह मुद्रा आज एशिया की सबसे सुरक्षित मुद्रा के रूप में उभर रही है। हालिया व्यापार युद्ध के चलते आई अस्थिरता का थाई बात पर बहुत अधिक असर नहीं पड़ा, जबकि भारतीय रुपये और दक्षिण कोरियाई वोन में लगभग 3% की गिरावट आई। थाईलैंड के बढ़ते चालू खाता अधिशेष (सरप्लस) और रिकार्ड स्तर पर पहुंचे विदेशी मुद्रा भंडार को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि थाई बात में आई इस स्थिरता पर निकट भविष्य में कोई संकट नहीं आएगा।

यूएस फेडरल, यूएस के राष्ट्रपति और चीनी युआन के बीच जारी तिहरे संघर्ष से दुनिया भर के उभरते हुए बाजार प्रभावित हुए हैं। हालांकि ताइवान और दक्षिण कोरिया का भी चालू खाता अधिशेष है, लेकिन आपूर्ति श्रृंखला के मामले में वैश्विक व्यापार युद्धों से थाईलैंड सीधे प्रभावित नहीं होता है।

- यथा 27 जून, 2019 को बेंचमार्क सेट इंडेक्स लगभग 7% बढ़ा है, जो 2012 के बाद इसकी सर्वश्रेष्ठ मासिक स्थिति है। यह एशिया में सबसे अच्छी बढ़त है।
- थाई बात में 3% से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है और यह छह वर्ष के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह एशिया की शीर्ष मुद्रा के स्थान पर अब वोन को सीधी टक्कर दे रहा है।
- स्थानीय-मुद्रा बॉन्डों में 5% से अधिक का रिटर्न मिला है, जो एशिया की उभरती हुई समतुल्य अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।

थाईलैंड के बाजारों में जून 2019 में 4 अरब यूएस डॉलर का विदेशी निवेश अंतः प्रवाह रहा और केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर में कटौती न किए जाने से स्थानीय मुद्रा और बॉन्डों को भी मजबूती मिली। लेकिन बैंक ऑफ थाईलैंड ने भी थाई बात की मजबूती को लेकर चिंता जताई है और आर्थिक वृद्धि में गिरावट आने की आशंकाओं के बीच कुछ उपाय भी किए हैं।

हांगकांग डॉलर

हांगकांग और चीन के अच्छे आर्थिक संबंधों के चलते हांगकांग की मुद्रा ग्रीनबैक (यू एस डॉलर) से पेग्ड होते हुए भी चीन से आर्थिक नजदीकी संबंधों के चलते युआन से काफी प्रभावित है। 5 अगस्त, 2019 को इसमें साढ़े तीन वर्षों की सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई जिसने पूरे एशिया को प्रभावित किया हांगकांग डॉलर का 12 माह का फॉरवार्ड पॉइंट 6 अगस्त, 2019 को 163 तक पहुंच गया, जो इस बात का संकेत है कि कुछ वैश्विक हेज फंड इस मुद्रा के विरुद्ध सट्टा लगा रहे हैं। 2017 के बाद से यह सर्वाधिक स्तर रहा।

इससे स्थानीय उधारी मूल्यों पर भी असर पड़ा, जिससे दुनिया के सबसे कम किफायती आवास बाजारों में से एक में मॉर्टगेजों को मजबूती मिली। लिक्विडिटी कम होने से ब्याज दरों पर पहले दबाव है, जिससे ये दरें जुलाई में दस वर्षों में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं। हाइबोर के नाम से जानी जाने वाली एक माह की हांगकांग डॉलर अंतरबैंक दरें 6 अगस्त, 2019 को 2008 के बाद से सर्वोतच्च स्तर पर रहीं।

वित्तीय संकट के बाद से हांगकांग में ब्याज दरें काफी कम रही थीं और वित्तीय प्रणाली के इर्द-गिर्द फंसी बड़ी राशि से स्टॉक और प्रॉपर्टी बाजारों में उछाल आई। अब स्टॉक गिर रहे हैं और जुलाई में घरों की बिक्री के मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में 32% की गिरावट आई और घरों की बिक्री की संख्या 21% कम हुई।

हांगकांग का ट्रैक रिकार्ड रहा है कि यह वित्तीय संकट के समय प्रत्यास्थता की स्थिति अपनाता है। 1990 के दशक के अंत के वर्षों के दौरान एशिया के वित्तीय अंतःस्फोट से 2003 के एसएआरएस तक और 2008 के वैश्विक ऋण संकट तक हांगकांग इससे बाहर निकलते हुए मजबूती के साथ खड़ा रहा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि यह तस्वीर निकट भविष्य में ही बदलने वाली है, किन्तु हालिया अस्थिरता से निवेशकों के लिए हांगकांग की आस्तियों के लिए चिंता से बाहर निकल पाना असंभव हो रहा है।

सिंगापुर डॉलर

सिंगापुर के मुद्रा बाजार में ब्याज दरों और मुद्रा में आती गिरावट केंद्रीय बैंक द्वारा पॉलिसी में नरमी बरतने की ओर संकेत करती है।

- लघु अवधि की ब्याज दरें बताती हैं कि सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकारी स्थानीय डॉलर की विनमय दर के लिए लक्ष्य को किस प्रकार बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं।
- दी गई त्रैमासिक अंतरबैंक दर में अब तक बढ़ोत्तरी देखी जा रही थी। इस बढ़ोत्तरी से लिक्विडिटी में आती कमी के संकेत मिलते हैं, क्योंकि एमएएस एनईईआर को बनाए रखने के लिए काम करता है।
- पिछले कुछ दिनों में साइबोर में अचानक गिरावट आई है और एसजीडी एनईईआर अपने अनुमानित स्तर से नीचे की ओर जा रहा है।
- यह एमएएस की ओर से संभावित किसी त्वरित घोषणा का संकेत हो सकता है कि पॉलिसी में कोई परिवर्तन होने वाला है।

नोटः एमएएस द्वारा वर्ष में दो बार पॉलिसी की घोषणा की जाती है। एक बार अप्रैल में और दूसरी बार अक्टूबर में।

सिटीग्रुप के अनुसार, यदि यूएस मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है तो एशिया प्रशांत में येन, सिंगापुर डॉलर और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर मुख्य रूप से लक्ष्य पर रहेंगे।

यद्यपि डॉलर के प्रभावी विनिमय दर सूचकांक में युआन का महत्त्वपूर्ण भार रहता है अतः और इसे खरीदा जा सकता है, तथापि यूएस और चीन के बीच जारी तनावपूर्ण परिवेश के बीच चीनी सरकार की प्रतिभूतियां रखना यूएस के लिए राजनीतिक रूप से अनुपयुक्त होगा।

फेडरल रिज़र्व द्वारा दरों में कटौती के बावजूद वर्ष 2002 से डॉलर का व्यापार-भारित सूचकांक सर्वोच्च रहा और कयास लगाए गए कि ट्रंप प्रशासन ग्रीनबैक को कमजोर कर सकता है। लेकिन चीन ने भी युआन को गिरने दिया और यह गिरते हुए एक दशक के दौरान पहली बार 7 युआन प्रति डॉलर से नीचे चला गया और देश को ट्रेजरी विभाग को मुद्रा मैनिपुलेटर का तमगा देना पड़ा।

येन पहले से ही यूएस के निशाने पर रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई और सिंगापुर डॉलर अपनी लिक्विडिटी स्थिति के चलते खरीदे भी जा सकते हैं।

चुनिंदा देशों का आर्थिक परिदृश्य

बांग्लादेश

बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के 2018-19 में 8.1% की वृद्धि दर से बढ़ने की उम्मीद है। यह वृद्धि रेडीमेड कपड़ों के निर्यातों में वृद्धि के चलते जताई जा रही है। 2020-23 के दौरान आर्थिक वृद्धि दर के औसत 7.8% रहने की उम्मीद है। बुनियादी ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश, विशेष रूप से परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से आर्थिक वृद्धि को विस्तार मिलेगा। बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों से पूँजी प्रवाह से इन बड़ी परियोजनाओं को निधि मिलने की उम्मीद है। अच्छे रेमिटैंस अंतःप्रवाह के साथ निजी खपत से भी इस अवधि के दौरान आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा। मुद्रा स्फीति दर के 2019 में औसतन 5.5% रहने के आसार हैं। वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट के साथ, 2020 में मुद्रा स्फीति दर के गिरकर 5% रहने की उम्मीद है। इसके बाद निजी खपत और वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोत्तरी के चलते 2021-23 के दौरान इसके औसतन 5.3% रहने के आसार हैं। बांग्लादेश आयातित ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर है और बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में खर्च बढ़ने के साथ पूंजीगत उपकरणों का आयात भी बढ़ा है। परिणामतः 2020-23 के दौरान बांग्लादेश के चालू खाते में घाटा रहने की आशंका है और यह घाटा जीडीपी का 2.2% रहने का पूर्वानुमान है। चालू खाता घाटा लगातार बने रहने से बांग्लादेश की मुद्रा टका के भी अवमूल्यन की आशंका है। इस प्रकार टका के 2018 में एक यूएस डॉलर के मुकाबले 83.5 के स्तर से गिरकर 2023 में एक यूएस डॉलर के मुकाबले 90.5 टका तक गिरने की आशंका है।

चिली

चिली उच्च आय अर्थव्यवस्था वाला एक खुला बाजार है। यहां की जीडीपी वृद्धि दर 2018 की 4% की तुलना में 2019 में गिरकर 2.6% रही। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अस्थिरता के चलते चिली के निर्यातों की मात्रा में भी गिरावट आई। 2021-23 के दौरान चिली की औसत वृद्धि दर 3.2% के आसपास रहने के आसार हैं। यह वृद्धि दर तांबे (चिली से निर्यात होने वाला प्रमुख मद) की बढ़ती कीमतों, वैश्विक व्यापार में सुधार और बेरोजगारी में गिरावट आने से निजी खपत में वृद्धि के चलते रहेगी। बिजली और खाद्य उत्पादों की कीमतें सामान्य बने रहने से उपभोक्ता मूल्य मुद्रा स्फीति नियंत्रण में रहेगी। 2019 में इसके औसतन 2.3% के आसपास रहने के आसार हैं। 2020-23 के दौरान मुद्रास्फीति 2-4% के लक्ष्य के अनुरूप रहेगी। तांबे की कीमतों में परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक जोखिमों के चलते चिली की मुद्रा पेसो प्रभावित हो सकती है। तथापि, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और तांबे की बढ़ती कीमतों के चलते पेसो के 2023 में एक यूएस डॉलर के मुकाबले 695.7 से 664.5 के बीच रहने की उम्मीद है। चिली का व्यापार अधिशेष (सरप्लस) है, लेकिन सेवा और प्राथमिक आय ठागे के चलते इसका चालू खाता घाटे में है। चिली से निर्यातों में बढ़ोत्तरी होने और तांबे की कीमतें बढ़ने के चलते 2023 में चालू खाता घाटा जीडीपी का 1.9% रहने के आसार हैं, जो 2018 में जीडीपी का 3.1% था।

इथियोपिया

इथियोपिया की जीडीपी वृद्धि दर 2019 में 7.4% रहने की उम्मीद है। लगातार जारी वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के परिवेश में इथियोपिया की अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ने के चलते देश में विदेशी निवेश आने की उम्मीद जताई जा रही है। देश में विनिवेश जैसे निरंतर होते आर्थिक सुधारों से 2019-23 के दौरान औसत विकास दर प्रतिवर्ष 7.6% रहने की उम्मीद है। वैश्विक खाद्य मूल्यों के 2020-21 में बढ़ने से कृषि और कृषि-खाद्य उद्योग को लाभ मिलेगा। तथापि, इस क्षेत्र पर मौसम की मार भी पड़ सकती है, इसलिए कृषि क्षेत्र को लेकर थोड़ी अनिश्चितता बनी रहती है। लेकिन बिजली की आपूर्ति बढ़ने और पूंजीगत माल के आयात के नियमों में नरमी बरते जाने से औद्योगिक क्षेत्र के गति पकड़ने की उम्मीद है। मुद्रा स्फीति दर 2018 के 13.8% से घटकर 2020 तक 8.3% तक हो जाने की उम्मीद है। इससे खाद्य पदार्थों और तेल की कीमतों में भी गिरावट आने की आशा है। इथियोपिया का केंद्रीय बैंक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया का पालन करता है और अपनी मुद्रा बिर को धीरे-धीरे अवमूल्यित होने देता है। बिर के 2023 में एक यूएस डॉलर के मुकाबले 34.12 तक गिरने के आसार हैं, जिसका मूल्य 2018 में एक यूएस डॉलर के मुकाबले 27.43 था। इथियोपिया को बड़े चालू खाता घाटा का सामना करना पड़ रहा है और 2018 में जीडीपी का 7.5% रहा। कच्चे तेल की वैश्विक स्तर पर गिरती कीमतों और निर्यातों के बढ़ने के चलते इथियोपिया का व्यापार घाटा गिरने की उम्मीद है। इसलिए चालू खाता घाटा भी 2023 तक कम होकर 4.9% तक होने की उम्मीद है।

रूस

रूस का वास्तविक जीडीपी 2018 में 2.2% की दर से बढ़ा, जो 2012 के बाद से सर्वोच्च दर है। यह वृद्धि मुख्य रूप से निर्माण और उत्खनन जैसे क्षेत्रों में वृद्धि के चलते रही। लेकिन इस वृद्धि दर में गिरावट की आशंका है और 2019 में इसके 1.3% और 2020 में 1.5% रहने के आसार हैं। 2021-23 के दौरान औसत वृद्धि दर प्रतिवर्ष 1.8% रहेगी। श्रमबल में आती कमी, प्राकृतिक संसाधनों पर भारी निर्भरता और निम्न उत्पादकता से आर्थिक वृद्धि को झटका लगेगा। वर्ष 2015 से मध्य 2018 के दौरान रूस को मुद्रा अवस्फीति का भी सामना करना पड़ा था। फिर 2018 में मुद्रास्फीति दर 4.3% हो गई और 2019 में वैट बढ़ने से इसके 5.1% तक बढ़ने के आसार हैं। यूएस प्रतिबंधों के चलते रूबल का मूल्य यूएस डॉलर के मुकाबले औसतन 62.7 रहा, जबकि 2017 में एक यूएस डॉलर के मुकाबले रूबल का मूल्य 58.3 था। रूस का चालू खाता अधिशेष (सरप्लस) अन्य निर्यातों के साथ-साथ तेल का निर्यात बढ़ने के चलते 2018 में जीडीपी का 6.9% हो गया, जो 2017 में मात्र 2.1% था। अब हाइड्रोकार्बन के अच्छे निर्यातों के बलबूते 2021-23 के दौरान चालू खाता अधिशेष बने रहने की उम्मीद है।

वस्तु व्यापार

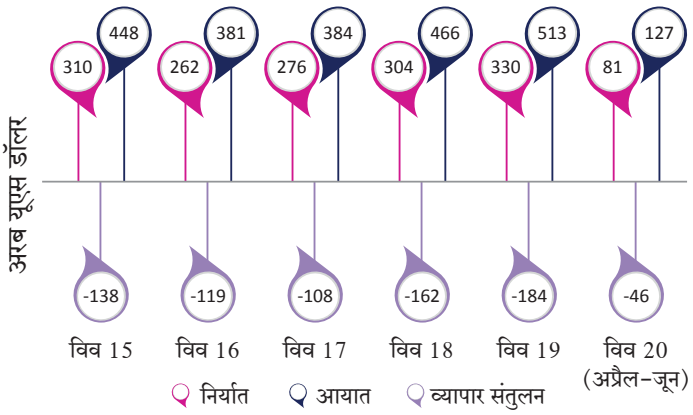

स्रोतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

सेवा व्यापार

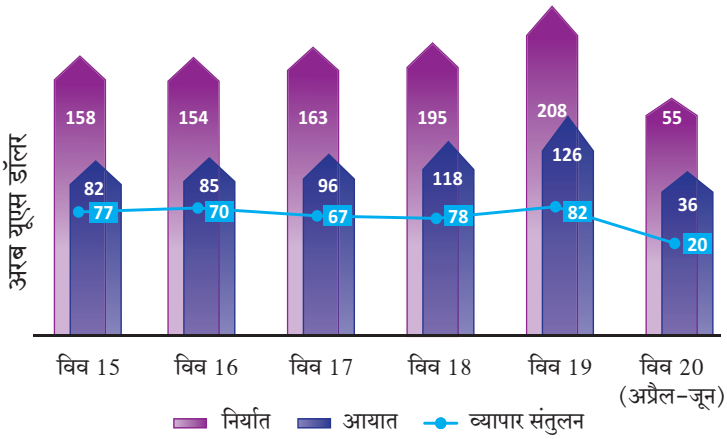

स्रोतः भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह

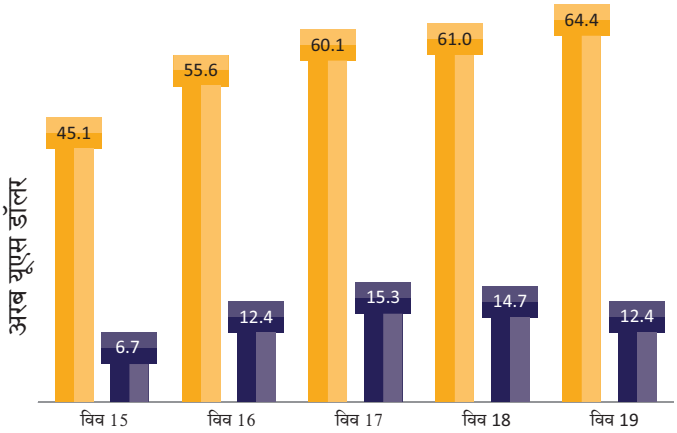

स्रोतः उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा आरबीआई

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (सीपीआई)

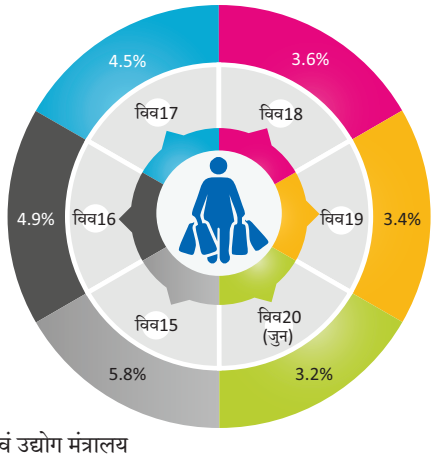

स्रोतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

चालू खाता घाटा

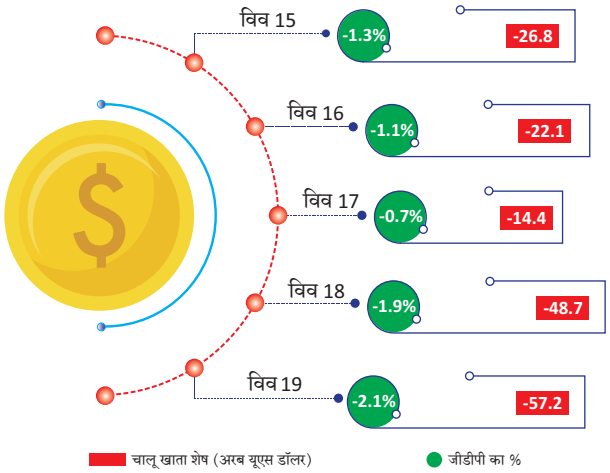

स्रोतः आरबीआई

क्षेत्रवार उत्पादन

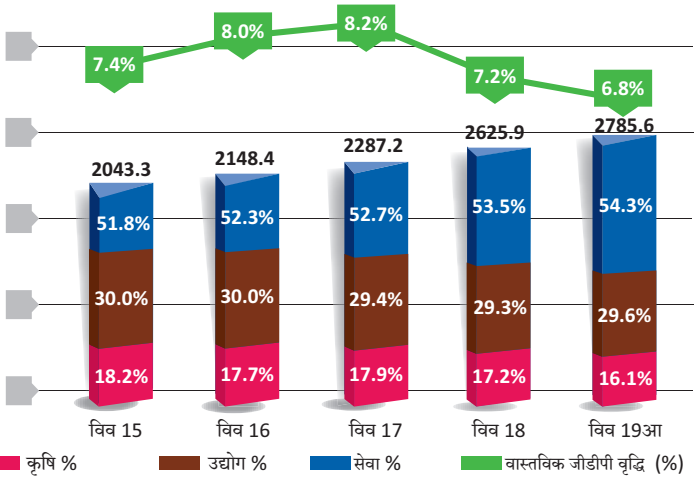

स्रोतः आईआईएफ एवं एमओएसपीआई

नोटः आ– आकलन

व्यापार और भागीदारी अवसर

व्यापार अवसर

भदोही के कालीन

एक सूक्ष्म उद्यम, जो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कालीन निर्यात करता है। ये कालीन डिजाइन और फैशल में वैश्विक स्तर के हैं। साथ ही बुनाई किए हुए ये कालीन घरेलू बाजार के लिहाज से भी अनूठे हैं।

बस्तर

पारंपरिक ढोकरा कला के विनिर्माता और निर्यातक, जो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक आदिवासियों द्वारा प्राचीन ढोकरा परंपरा के अनुसार बनाए जाते हैं। यह प्रक्रिया बीते 200 वर्षों से चली आ रही है।

पैचवर्क

ग्रामीण दस्तकारों के स्वयं सहायता समूह द्वारा हस्तनिर्मित वस्त्र व लाइफस्टाइल उत्पाद। ये वंचित समुदाय की महिलाओं के कौशल विकास और दुनिया में उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है।

कच्छ की पॉटरी

दस्तकारों व डिजाइनरों द्वारा बनाए गए उत्पाद; बाजार की जरूरतों, पैकेजिंग और मार्केटिंग में उनकी मदद करना। कच्छ के अनूठे दीयों और टेराकोटा वस्तुओं की कैटरिंग।

ढोकरा

सामुदायिक संगठन जो छोटे दस्तकारों के लिए स्थायी आजीविका विकसित करने और आदिवासी तथा पारंपरिक शिल्पकारों के कौशल विकास के लिए प्रयासरत है।

पैठनी

हथकरघा निगम, जो राज्य की पैठनी कला के लिए हथकरघा बुनकरों को रोजगार प्रदान कर रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य दस्तकारों और बुनकरों का समग्र कल्याण और विकास करना है।

भागीदारी अवसर

परियोजनाओं में अवसर

(i) बांग्लादेश सरकार के पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड द्वारा बांग्लादेश में एक अंतरराष्ट्रीय टेंडर जारी किया गया है। यह टेंडर 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइन परियोजना के लिए है और इसके डिजाइन, आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, परीक्षण और डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन को चालू करने के लिए इसे बांग्लादेश सरकार द्वारा निधि प्राप्त है।

इच्छुक पार्टियां हमारी मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार संपर्क कर सकती हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क कीजिए: फोन: 2217 2600, एक्सटेंशन: 2822/2737, फैक्स: 2218 8268, ईमेल: mas@eximbankindia.in